

संक्षिप्त समाचार

मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर में ई-फाइलिंग और स्कैनिंग सेन्टर शुरू

भोपाल। न्यायपालिका के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में एक आगे बढ़ते हुए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में आज ई-फाइलिंग और स्कैनिंग सेन्टर का शुभारंभ हुआ। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजीव सचदेवा ने आज मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के माननीय न्यायाधीशों और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के बार एसोसिएशनों के पदाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं की उपस्थिति में उच्च न्यायालय में ई-फाइलिंग और स्कैनिंग केंद्र का उद्घाटन किया। स्कैनिंग सेन्टर की सुविधा से अधिवक्तावादी व्यक्तिगत रूप से नए मामले दाखिल करने के साथ-साथ लबित मामलों में आवेदन/उत्तर/प्रतिक्रिया/दस्तावेज/वकालतनामा आदि ई-फाइलिंग केंद्र से दाखिल कर सकेंगे। ई-फाइलिंग सेन्टर में वे सभी सुविधाएं मौजूद हैं जो ऑनलाइन मामला दाखिल करने के लिए आवश्यक हैं। केंद्र में सहायक व्यक्ति या सुविधाकर्ता और स्कैनर जैसी विशेष सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। बैठने की उचित व्यवस्था की गई है। ई-फाइलिंग सेन्टर पूरी तरह से वातानुकूलित है। त्वरित ई-फाइलिंग के लिए वित्तीय लेनदेन हेतु त्वरित प्रतिक्रिया (क्यू. आर.) कोड प्रदान किया गया है। मुकदम की ई-फाइलिंग के संबंध में अधिवक्ताओं/वादियों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। यदि मामला ई-फाइलिंग मोड़यूल द्वारा दायर किया जाता है। यदि प्रकरण में कोई कमी न हो तो इसे दाखिल करने की तिथि से तीसरे कार्य दिवस पर तत्काल सूचीबद्ध किया जाएगा। कमी होने की स्थिति में कमी को हटाने की तिथि से तीसरे कार्य दिवस में सूचीबद्ध किया जायेगा। ई-फाइलिंग सेन्टर मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय में ई-फाइलिंग को अत्यधिक बढ़ावा देगा और इससे सरकारी खजाने का पैसा भी बचेगा जो पहले मामलों को स्कैन करने या डिजिटल बताने में खर्च होता था। इससे कागजी कार्रवाई भी कम होगी और यह पर्यावरण के अनुकूल पहल है।

**उपमुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने सागर में किया
ध्वजारोहण ,परेड की सलामी ली**

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल सागर में स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रदेशवासियों के नाम संदेश का वाचन किया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री ताराचंद जैन और लोकतंत्र सेनानी एडवोकेट कृष्ण वीर सिंह ठाकुर को शौल, श्रीफल और पुष्पहार से सम्मानित किया। शासकीय उ.मा.वि., उत्कृष्ट विद्यालय, सीएम राइज उ.मा.वि. सागर, सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल एवं लिटिल स्टार मेमोरियल स्कूल के छात्र-छात्राओं द्वारा आकर्षित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। खेल युवा कल्याण विभाग के खिलाड़ियों द्वारा मलखंभ का अद्भुत प्रदर्शन किया गया। जेएनपीए, जिला पुलिस बल, पुलिस प्रशिक्षण बल मकरोनिया, होम गार्ड सागर, जिला पुलिस बल महिला सागर, 11 एमपी बटालियन एनसीसी बालक, 7 एमपी बटालियन बालिका, शौर्य दल सागर एवं पुलिस बैंड प्लाटून द्वारा आकर्षक मार्चापास्ट किया गया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों- कर्मचारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाले छात्र-छात्राओं एवं मार्च पास्ट में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों समूह को पुरस्कृत किया।

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग में किया ध्वजारोहण

भोपाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने 78वें



स्वतंत्रता दिवस पर राज्य निर्वाचन आयोग में ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद सभी ने राष्ट्रगान किया। श्री सिंह ने सभी को स्वाधीनता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दीं। इस दौरान सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री अम्भिके सिंह सहित निर्वाचन आयोग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

भोपाल। उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल सागर के बुंदेलखण्ड मेडिकल कॉलेज पहुंचे और वहां बनने वाले सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के निर्माण के संबंध में समीक्षा की। इस दौरान विधायक श्री शैलेंद्र जैन एवं बीएमसी डीन डॉ पीएस ठाकुर ने उन्हें विस्तार से प्रोजेक्ट संबंधी जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने आयुक्त चिकित्सा शिक्षा से भी फौन पर चर्चा कर प्रस्ताव की पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सागर बहुत बड़ा सेंटर है और हम यहां पर मेडिकल की सीट्स 100 से बढ़ाकर 250 करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अब सागर जिले का प्रभारी मंत्री हूं और प्रतिमाह यहां आऊंगा। इसलिए बीएमसी के सारे विषय प्राथमिकता से पूर्ण किए जाएं। उन्होंने बीएमसी में कैथेचैर, न्यूरोलॉजी एवं कैंसर हॉस्पिटल की प्रगति को जाना और प्लानिंग की समीक्षा की। विधायक श्री जैन ने उन्हें बताया कि रीवा मेडिकल कॉलेज में कैथेचैर लैब की नई मशीन का ऑर्डर किया गया है, यदि सागर की मशीन जाए तो सुविधा र शुक्ल ने आयुक्त निर्देशित करते हु मशीन भी इसी से और प्राथमिकता बुंदेलखण्ड मेडिकल को पूरा करते हु टेंडर जारी क बीएमसी में एम सीटी स्कैन मशीन रेडियोलॉजी विभाग लिए एसआर शिक्षा भी चर्चा की जिससे और भी हैंड मिल चौक अस्पताल अपग्रेड होने पर शुरू करने के निवेदित उप मुख्यमंत्री श्री संदीप जी आर व सीएमएचओ को के निर्देश दिये गये मारटेलिटी रेट (ए मारटेलिटी रेट (

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने राजभवन में किया ध्वजारोहण

भोपाल। राशीय उत्सव स्वतंत्रता दिवस पर राजभवन में गरिमामय समारोह आयोजित हुआ। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने समारोह में ध्वजारोहण किया। खुले आकाश में तिरंगे गुब्बारे उड़ाकर स्वतंत्रता का जश्न मनाया। समारोह में पुलिस बैंड ने राष्ट्रधुन का वादन किया। राज्यपाल श्री पटेल ने राजभवन सचिवालय के अधिकारी-कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। नन्हे-मुन्ने बच्चों के साथ तिरंगे गुब्बारे खुले आकाश में मुक्त किये। बच्चों एवं कर्मचारियों को मिष्ठान का वितरण किया। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल आज मध्यप्रदेश की सुप्रसिद्ध हस्तशिल्प कला चंदेरी के बने हुए वस्त्र का साफा धारण कर राजभवन के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए। राजभवन के स्वतंत्रता दिवस समारोह में राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री मुकेश चंद गुप्ता, सदस्य सचिव जनजातीय प्रकोष्ठ श्री अमरपाल सिंह, राज्यपाल के अपर सचिव श्री उमाशंकर भार्गव, परिसहाय द्वय श्री शशांक, श्री अतुल शर्मा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी श्री अरविन्द पूरोहित, विशेष सहायक श्री विपुल पटेल, नियंत्रक हाउस होल्ड श्रीमती शिल्पी दिवाकर, सुरक्षा अधिकारी श्री इंद्रजीत सिंह चावड़ा, जनजातीय प्रकोष्ठ के सदस्य सहित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।



विद्यानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने मुरैना में किया ध्वजारोहण



भोपाल। विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर मुरैना के पुलिस परेड ग्राउण्ड पर आयोजित समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने जनता के नाम मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने समुद्घि के प्रतीक रंग-बिरंगे गुब्बारे आसमान में छोड़े। पुलिस बल द्वारा हर्ष फायर किया गया। स्कूली बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दीं। विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र वितरित किये। समारोह में स्थानीय जन-प्रतिनिधि, नागरिक एवं विद्यार्थीगण उपस्थित थे।

स्वतंत्रता सेनानियों के अथक परिश्रम, त्यग और बलिदान का परिणाम है स्वतंत्रता दिवस

भोपाल। सागर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री तथा सागर जिले के प्रधारी मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने ध्वजारोहण परेड की सलामी ली। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का प्रदेशवासियों के नाम संदेश का वाचन किया। देश के स्वतंत्रता सेनानियों के अथक परिश्रम, त्याग और बलिदान का परिणामस्वरूप मिली स्वतंत्रता को सागर जिले में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री ताराचंद जैन और लोकतंत्र सेनानी एडवोकेट कृष्ण वीर सिंह ठाकुर को शॉल, श्रीफल और पुष्पहार से सम्मानित किया। शासकीय उ.मा.वि., उत्कृष्ट विद्यालय, सीएम राइज उ.मा.वि. सागर, सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल एवं लिटिल स्टार मेमोरियल स्कूल के छात्र-छात्राओं द्वारा आकर्षित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। खेल युवा कल्याण विभाग की

भोपाल। भोपाल के गौहर
महल में राज्य स्तरीय
हस्तशिल्प एवं हाथकरघा
प्रदर्शनी एवं सावन मेले का
आयोजन किया जा रहा है।
प्रदर्शनी एवं सावन मेला 19
अगस्त तक चलेगा। इसमें
लगभग 55 से ज्यादा
शिल्पकार अपनी कलाकृतियों
का प्रदर्शन एवं विक्रय कर रहे
हैं।

सावन मेले में महिलाओं
की अभिरूचि के अनुसार नई
डिजाइन की चूड़ियाँ, मेहरी,
सौन्दर्य सामग्री सहित झूले भी
रखे गये हैं। यहां 1930 के
दशक की रेशम, किनार,
चन्देरी, मसलिन, कॉटन
साड़ियाँ, देवी अहिल्या बाई
होल्कर नगरी की महेश्वर
साड़ियाँ, मध्यप्रदेश का विशेष
बाग प्रिंट जिसे 12 जड़ी
बूटियों से प्रिंट किया गया है,
सावन मेले में रखी गयी हैं।
पंच धातु, बेल मेटल की
मरियाँ तथा शिफान मलबरी

उप मुख्यमंत्रा श्रा दवड़ा न जबलपुर म किया ध्वजारोहण

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवडा ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस परेड ग्राउंड जबलपुर में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। श्री देवडा ने खुली जीप में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया। श्री देवडा ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन किया। सुरक्षा बल की टुकड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवडा ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके परिजन तथा लोक तंत्र सेनानियों का शात और श्रीफल भेंटकर सम्मान किया। स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों पर मनोहारी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। उप मुख्यमंत्री श्री देवडा ने मार्च पास्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किये।



सागर बीएमसी में सुपर स्पेशलिटी सेवाएं गौहर महल में 19 अगस्त तक जारी है सावन मेला अविलंब शुरू करना मेरी प्राथमिकता

भोपाल। उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल सागर के बुंदेलखण्ड मेडिकल कॉलेज पहुंचे और वहां बनने वाले सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के निर्माण के संबंध में समीक्षा की। इस दौरान विधायक श्री शैलेंद्र जैन एवं बीएमसी डीन डॉ पीएस ठाकुर ने उन्हें विस्तार से प्रोजेक्ट संबंधी जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने आयुक्त चिकित्सा शिक्षा से भी फौन पर चर्चा कर प्रस्ताव की पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सागर बहुत बड़ा सेंटर है और हम यहां पर मेडिकल की सीट्स 100 से बढ़ाकर 250 करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अब सागर जिले का प्रभारी मंत्री हूं और प्रतिमाह यहां आऊंगा। इसलिए बीएमसी के सारे विषय प्राथमिकता से पूर्ण किए जाएं। उन्होंने बीएमसी में कैथेचैर, न्यूरोलॉजी एवं कैंसर हॉस्पिटल की प्रगति को जाना और प्लानिंग की समीक्षा की। विधायक श्री जैन ने उन्हें बताया कि रीवा मेडिकल कॉलेज में कैथेचैर लैब की नई मशीन का ऑर्डर किया गया है, यदि सागर की मशीन जाए तो सुविधा र शुक्ल ने आयुक्त निर्देशित करते हु मशीन भी इसी से और प्राथमिकता बुंदेलखण्ड मेडिकल को पूरा करते हु टेंडर जारी क बीएमसी में एम सीटी स्कैन मशीन रेडियोलॉजी विभाग लिए एसआर शिक्षा भी चर्चा की जिससे और भी हैंड मिल चौक अस्पताल अपग्रेड होने पर शुरू करने के निवेदित उप मुख्यमंत्री श्री संदीप जी आर व सीएमएचओ को के निर्देश दिये गये मारटेलिटी रेट (ए मारटेलिटी रेट (

सागर की मशीन भी इसी के साथ आ जाए तो सुविधा रहेगी। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने आयुक्त चिकित्सा शिक्षा को निर्देशित करते हुए कहा कि सागर की मशीन भी इसी सासाह ऑर्डर की जाए और प्राथमिकता के आधार पर सागर के बुद्धेलंखड मेडिकल कालेज की कमियों को पूरा करते हुए डीपीआर तैयार कर टेंडर जारी करें। इसके अतिरिक्त बीएमसी में एमआरआई मशीन एवम सीटी स्केन मशीन अविलंब लगाई जाए। रेडियोलॉजी विभाग में सोनोग्राफी के लिए एसआर शिप शुरू करने को लेकर भी चर्चा की जिससे सोनोग्राफी के लिए और भी हैंड मिल सकेंगे। उन्होंने चमेली चौक अस्पताल के जीर्णधार उपरांत अपग्रेड होने पर वहां भी सामान्य प्रसव शुरू करने के निर्देश दिए। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कलेक्टर श्री संदीप जी आर को जिम्मेदारी देते हुए सीएमएचओ को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने मेटरनल मोरटेलिटी रेट (एमएमआर) और ईफेंट मोरटेलिटी रेट (आईएमआर) का मुद्दा उठाया और इसे कम करने की दिशा में काम करने की जरूरत बताई। जिस पर डीन डॉ पी एस ठाकुर ने जानकारी दी कि स्ट्रीरोग विभाग में प्राध्यापक के अतिरिक्त पदों पर भर्ती के लिए शासन को प्रस्तावक भेजा है और यह पद भर जायेंगे तो स्ट्रीरोग विभाग में पीजी सीट में बृद्धि हो सकेगी साथ ही गर्भवती महिलाओं की बेहतर देखभाल में भी मदद मिलेगी। उपमुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने क्रिटिकल केयर यूनिट को बीएमसी अस्पताल की दूसरी मजिल में खाली पड़ी जगह पर बनाने का सुझाव दिया ताकि उसी के साथ कैंसर अस्पताल के बंकरों का भी निर्माण कर कैंसर मरीजों को इलाज की सुविधा दी जा सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने न्यूरोसर्जन के पद निर्माण के मुद्दे पर सीएमई श्री तरुण पिथोडे से बात कर शीघ्र पद जारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने बैठक के दौरान मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विशेषज्ञ डॉ. सुनील सक्सेना की सराहना करते हुए कहा कि उनके द्वारा कैंसर एवं अन्य बीमारियों में की जा रही सर्जरी का कार्य सराहनीय है।

शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए समग्र एवं आधार से ई-केवार्डसी आवश्यक

भोपाल। सभी आमजन को सूचित किया गया है कि शासन द्वारा संचालित सभी योजनाओं एवं शासकीय कार्यों का लाभ लेने के लिये सभी खाताधारक, भूमि स्वामियों, प्लॉट-भूखण्ड, मकान मालिकों जिनके नाम खसरा रिकार्ड में दर्ज हैं उन्हें अपने-अपने भू-खण्ड एवं कृषि भूमियों का समग्र आई.डी. एवं आधार कार्ड से ई-केवाईसी कराना आवश्यक है। अगर आप अपनी भूमियों की हेरा-फेरी एवं जमीन संबंधी गड़बड़ियों से बचना चाहते और अपने भूखण्ड, मकान, दुकान कृषि भूमि को सुरक्षित रखना चाहते हो तो आप सभी अपने नजदीकी सीएससी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर अपनी-अपनी कृषि भूमियों, भूखण्डों, प्लाट एवं मकानों की ई-केवाईसी अवश्य करवाएँ और शासन की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और होने वाली धोखाधड़ी तथा असुविधा से बच सकते हैं। ई-केवाईसी के लिए अपने साथ समग्र आई.डी.आधार कार्ड, जन्म तिथि से संबंधित कोई भी दस्तावेज, मोबाइल नम्बर, खसरा नकल साथ में लें जाएँ और शीघ्र अतिशीघ्र केवाईसी करवाएँ। मोबाइल तथा कम्प्यूटर से ईकेवाईसी करने के लिए पर लॉगइन करें। इसके पश्चात समग्र पोर्टल पर क्लिक करें राजस्व महाअभियान अंतर्गत ई-केवाईसी समग्र आईडी प्रविष्ट करें पंजीकृत मोबाइल से प्राप्त ओटीपी दर्ज करें। इसके बाद भूमि संबंधी जानकारी जैसे जिला, तहसील, ग्राम, खसरा नंबर प्रविष्ट करें तथा नाम सिलेक्ट करें आधार ओटीपी दर्ज करें। इसके बाद आपका ई-केवाईसी हो जाएगा।

विचार

आरक्षण के भीतर आरक्षण की व्यवस्था का अहम फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों-जनजातियों यानी एससी-एसटी समुदाय में आरक्षण के भीतर आरक्षण का रास्ता साफ करके आरक्षण की व्यवस्था को तार्किक, न्यायसंगत, समानतापूर्ण बनाने का सराहनीय कार्य किया है। न्यायालय के इस तरह के फैसले मिसाल ही नहीं, मशाल बन कर सामने आ रहे हैं, जिससे राष्ट्र की विसंगतियों एवं विडब्बनाओं से मुक्ति की दिशाएं उद्घाटित हो रही हैं। यह फैसला कई बिल्कुल अलग-अलग बजाहों से अहम माना जा रहा है। क्योंकि बड़ा सच यह है कि ओबीसी समाज की तरह एससी-एसटी समुदाय में भी कई जातियों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति न केवल कहीं कमज़ार है, बल्कि उहाँ अपने ही वर्ग की अन्य जातियों से भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। यह एक ऐसी सच्चाई है, जिससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। यह भी एक तथ्य है कि एससी-एसटी समुदाय में कई जातियां ऐसी हैं, जिन्हें आरक्षण का न के बराबर लाभ मिला है। ऐसा इसीलिए हुआ है, क्योंकि आरक्षण का अधिक लाभ इन वर्गों की अपेक्षाकृत समर्थ जातियों उठाती हैं। यही स्थिति ओबीसी में है। कई अति पिछड़ी जातियों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा है। राजनीतिक एवं संवैधानिक विसंगतियों के कारण ऐसा होता रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने जहाँ छह-एक के बहुमत से एससी-एसटी आरक्षण में कोटे के भीतर काटे को संविधानसम्मत बताया, वहीं चार न्यायाधीशों ने इन वर्गों के आरक्षण में उसी तरह क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने की भी आवश्यकता जताई, जैसी ओबीसी आरक्षण में है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से 2004 के पांच सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि एससी-एसटी समुदाय एक जैसा है और उनकी विभिन्न जातियों में कई भेद नहीं किया जा सकता। यह वस्तुस्थित नहीं थी, इस विसंगति को सुधार कर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायसंगत उपक्रम किया है। अब राज्यों एवं केन्द्र सरकार को बहुत सावधानी से कदम उठाने होंगे। इस ताजे फैसले के बाद अनेक राज्यों में जातिगत गणना की होड़ शुरू हो सकती है एवं राजनीति दलों में आरक्षण का मुद्दा नये आक्रामक रूप में उभर सकता है। लेकिन एक आदर्श समता, समानता एवं सुलुलनमूलक समाज-व्यवस्था को निर्मित करने की दिशा में कोर्ट का यह फैसला अहम है। संविधान पीठ के अनुसार, आरक्षण का मुख्य मकसद आर्थिक और सामाजिक समानता लाना है, पर इसके लिए शहर और गांव की सामाजिक हकीकत में अंतर के साथ आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखना जरूरी है। एससी समुदाय में भी दो बड़े वर्ग हैं, जिनमें गहरा फैसला है। बड़े अफसरों और बड़े वकीलों के बच्चों की तुलना में पैला ढोने वाले बच्चों से करना कैसे न्यायसंगत हो सकता है? इसलिए पीछे रह गई जातियों को मुख्यधारा में लाने के लिए ओबीसी की तर्ज पर एससी में भी कोटे के भीतर कोटे को न्यायाधीशों ने संविधानिक माना है। आज के समय में इस फैसले की जरूरत को समझा जा सकता है, लेकिन समस्या यह है कि देश में 140 करोड़ जनसंख्या की सामाजिक स्थिति और आर्थिक हैसियत के आंकड़े स्पष्ट तौर पर उपलब्ध नहीं हैं।

सत्ता हो विपक्ष, राजनीति तो स्वाभाविक है

उमेश चतुर्वेदी

विपक्षी कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने बजट को लेकर राजनीति की है। विपक्ष का आरोप है कि इस बजट में नीतीश कुमार और एन चंद्रबाबू नायडू ने अल्पमत सरकार को समर्थन देने की कीमत वसूली है। आरोप यह भी है कि सरकार बचाने के लिए बीजेपी ने बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज दिया है, जबकि अन्य राज्यों को कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। आरोप को बढ़ाते हुए विपक्ष यहाँ तक कह रहा है कि यह पूरे देश का बजट नहीं है। कांग्रेस तो यहाँ तक कह रही है कि मौजूदा बजट उसके चुनाव घोषणा पत्र की बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज दिया है, जबकि अन्य सरकार यहाँ तक कह रहा है कि यह बजट को बढ़ाते हुए राजनीतिक दल की अपनी विचारधारा है, उसका अपना एजेंडा होता है, उसका अपना वोट बैंक होता है। बजट हो या अन्य सरकारी फैसले, हर राजनीतिक दल और सरकार अपने कदम उठाते वक्त उनका ध्यान रखता है। इसके साथ ही हर राजनीतिक दल अपने भावी और लक्षित वोट बैंक को लुभाने के लिए विहाज से भी फैसले लेता है। हर राजनीतिक दल की चाहत होती है कि उसका मौजूदा वोट आधार बढ़े।



इस लिहाज से भी वह अपने राजनीतिक फैसले लेता है और उसकी भावनाएं भी अपनी नीतियों इसी हिसाब से बनती और बढ़ती हैं। इस नजरिए से देखें तो अगर मोदी सरकार ने नीतीश और नायडू के राज्यों को कुछ विशेष सहायताएं दी हैं तो कोई गलत नहीं है। अगर बिहार बाकी राज्यों की तुलना में पिछड़ा है, वह नायड़ा पलायन का देश झेलने को मजबूर है तो हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस देश के साथ कदमताल करने के लिए बिहार को अगर सहायिता देनी पड़ी तो दें। मदद का हाथ बढ़ाना पड़े तो बढ़ाए। अगर आंध्र प्रदेश को भी मदद की दरकार हो तो मिलनी चाहिए। ऐसी विवरणों के बाद अगर बिहार बाकी राज्यों की तुलना में पिछड़ा है, वह नायड़ा पलायन का देश झेलने को मजबूर है तो हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस देश के साथ कदमताल करने के लिए बिहार को अगर सहायिता देनी पड़ी तो दें। मदद का हाथ बढ़ाना पड़े तो बढ़ाए। अगर आंध्र प्रदेश को भी मदद की दरकार हो तो मिलनी चाहिए। ऐसी विवरणों के बाद अगर बिहार बाकी राज्यों की तुलना में पिछड़ा है, वह नायड़ा पलायन का देश झेलने को मजबूर है तो हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस देश के साथ कदमताल करने के लिए बिहार को अगर सहायिता देनी पड़ी तो दें। मदद का हाथ बढ़ाना पड़े तो बढ़ाए। अगर आंध्र प्रदेश को भी मदद की दरकार हो तो मिलनी चाहिए। ऐसी विवरणों के बाद अगर बिहार बाकी राज्यों की तुलना में पिछड़ा है, वह नायड़ा पलायन का देश झेलने को मजबूर है तो हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस देश के साथ कदमताल करने के लिए बिहार को अगर सहायिता देनी पड़ी तो दें। मदद का हाथ बढ़ाना पड़े तो बढ़ाए। अगर आंध्र प्रदेश को भी मदद की दरकार हो तो मिलनी चाहिए। ऐसी विवरणों के बाद अगर बिहार बाकी राज्यों की तुलना में पिछड़ा है, वह नायड़ा पलायन का देश झेलने को मजबूर है तो हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस देश के साथ कदमताल करने के लिए बिहार को अगर सहायिता देनी पड़ी तो दें। मदद का हाथ बढ़ाना पड़े तो बढ़ाए। अगर आंध्र प्रदेश को भी मदद की दरकार हो तो मिलनी चाहिए। ऐसी विवरणों के बाद अगर बिहार बाकी राज्यों की तुलना में पिछड़ा है, वह नायड़ा पलायन का देश झेलने को मजबूर है तो हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस देश के साथ कदमताल करने के लिए बिहार को अगर सहायिता देनी पड़ी तो दें। मदद का हाथ बढ़ाना पड़े तो बढ़ाए। अगर आंध्र प्रदेश को भी मदद की दरकार हो तो मिलनी चाहिए। ऐसी विवरणों के बाद अगर बिहार बाकी राज्यों की तुलना में पिछड़ा है, वह नायड़ा पलायन का देश झेलने को मजबूर है तो हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस देश के साथ कदमताल करने के लिए बिहार को अगर सहायिता देनी पड़ी तो दें। मदद का हाथ बढ़ाना पड़े तो बढ़ाए। अगर आंध्र प्रदेश को भी मदद की दरकार हो तो मिलनी चाहिए। ऐसी विवरणों के बाद अगर बिहार बाकी राज्यों की तुलना में पिछड़ा है, वह नायड़ा पलायन का देश झेलने को मजबूर है तो हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस देश के साथ कदमताल करने के लिए बिहार को अगर सहायिता देनी पड़ी तो दें। मदद का हाथ बढ़ाना पड़े तो बढ़ाए। अगर आंध्र प्रदेश को भी मदद की दरकार हो तो मिलनी चाहिए। ऐसी विवरणों के बाद अगर बिहार बाकी राज्यों की तुलना में पिछड़ा है, वह नायड़ा पलायन का देश झेलने को मजबूर है तो हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस देश के साथ कदमताल करने के लिए बिहार को अगर सहायिता देनी पड़ी तो दें। मदद का हाथ बढ़ाना पड़े तो बढ़ाए। अगर आंध्र प्रदेश को भी मदद की दरकार हो तो मिलनी चाहिए। ऐसी विवरणों के बाद अगर बिहार बाकी राज्यों की तुलना में पिछड़ा है, वह नायड़ा पलायन का देश झेलने को मजबूर है तो हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस देश के साथ कदमताल करने के लिए बिहार को अगर सहायिता देनी पड़ी तो दें। मदद का हाथ बढ़ाना पड़े तो बढ़ाए। अगर आंध्र प्रदेश को भी मदद की दरकार हो तो मिलनी चाहिए। ऐसी विवरणों के बाद अगर बिहार बाकी राज्यों की तुलना में पिछड़ा है, वह नायड़ा पलायन का देश झेलने को मजबूर है तो हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस देश के साथ कदमताल करने के लिए बिहार को अगर सहायिता देनी पड़ी तो दें। मदद का हाथ बढ़ाना पड़े तो बढ़ाए। अगर आंध्र प्रदेश को भी मदद की दरकार हो तो मिलनी चाहिए। ऐसी विवरणों के बाद अगर बिहार बाकी राज्यों की तुलना में पिछड़ा है, वह नायड़ा पलायन का देश झेलने को मजबूर है तो हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस देश के साथ कदमताल करने के लिए बिहार को अगर सहायिता देनी पड़ी तो दें। मदद का हाथ बढ़ाना पड़े तो बढ़ाए। अगर आंध्र प्रदेश को भी मदद की दरकार हो तो मिलनी चाहिए। ऐसी विवरणों के बाद अगर बिहार बाकी राज्यों की तुलना में पिछड़ा है, वह नायड़ा पलायन का देश झेलने को मजबूर है तो हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस देश के साथ कदमताल करने के लिए बिहार को अगर सहायिता देनी पड़ी तो दें। मदद का हाथ बढ़ाना पड़े तो बढ़ाए। अगर आंध्र प्रदेश को भी मदद की दरकार हो तो मिलनी चाहिए। ऐसी विवरणों के बाद अगर बिहार बाकी राज्यों की तुलना में पिछड़ा है, वह नायड़ा पलायन का देश झेलने को मजबूर है तो हर सरकार की जिम

युवा शक्ति, नारी सशक्तिकरण, गरीब कल्याण और किसान कल्याण मिशन प्रदेश के स्थापना दिवस से होंगे आरम्भ-मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 78वें स्वतंत्रता दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज भारत माता को स्वतंत्र करने के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीरों, राष्ट्रभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों का पुण्य-स्मरण करने का दिन है। प्रशासन जनोन्मुखी हो, नागरिक विकास और सामाजिक सद्विकार में भागीदार बनें, गरीबों के कल्याण की योजनाएं अंतिम पर्यांत तक पहुंचे ऐसी पुखुआ व्यवस्था करने के लिए हमारा सरकार किटबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व की पांचवीं अर्थव्यवस्था बनने के सफर को तय कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश, प्रधानमंत्री श्री मोदी के संकल्पों की सिद्धि में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव लाल परेड ग्राउण्ड भोपाल पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर लाल परेड ग्राउण्ड में ध्वजारोहण के बाद निरीक्षण वाहन से पेरेड का अवलोकन कर सलामी ली। परेड के सशस्त्र दलों ने तीन चरणों में हर्ष फायर किया। पुलिस बैंड ने राष्ट्रगान जन-गण-मन की धूम के साथ अन्य देशभक्ति के गीतों की धूमें प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पदक अलंकरण समारोह में पुलिस अधिकारी और कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा, सराहनीय सेवा और वीरता के लिए सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश के विकास में 4 वर्षों यथा युवा, महिला, किसान और गरीब को आधार स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया है। मध्यप्रदेश सरकार प्रधानमंत्री श्री मोदी के विचारों से प्रेरणा लेकर चार मिशन, युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण मिशन बनाकर काम करने जा रही है। मध्यप्रदेश के स्थानीय दिवस आगामी एक नवम्बर से यह मिशन अपना काम प्रारंभ करेंगे। युवा शक्ति मिशन में शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता, नेतृत्व विकास, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास की कार्य योजना तैयार कर मिशन मोड़ में कार्य किया जाएगा। गरीब कल्याण मिशन में स्व-रोजगार योजनाएं, सामाजिक सुविधा योजनाएं, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा आदि की दिशा में कार्य करेंगा। नारी सशक्तिकरण मिशन के तहत बालिका शिक्षा, लाडली, लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, लक्ष्मी परियों दीवी योजना, महिला स्व-सहायता समूहों के सशक्तिकरण आदि कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किए जाएंगे। किसान कल्याण मिशन ने देश के लिए जाएंगे।



में सरकार कृषि एवं उद्यानिकों को लाभ का व्यवसाय बनाने की दिशा में कार्य करेगी। किसानों को राहत प्रदान करने के साथ एवं कृषि की पैदावार बढ़ावा की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश का बजट अगले पांच वर्ष में दो गुना करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूँजीगत व्यय 60 हजार 689 करोड़ रुपये किया गया। वर्ष 2022-23 की तुलना में यह वृद्धि लगभग 29 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूँजीगत व्यय का लक्ष्य 64 हजार 738 करोड़ रुपये रखा गया है। वर्ष 2023-24 में 17 हजार से अधिक रोजगार के अवसर मुजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि युवाओं को सिर्फ पारंपरिक शिक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ए.आई.एसीन और कोडिंग जैसी नवीन तकनीकों की भी शिक्षा प्राप्त करनी है। इसके लिए उच्च शिक्षा में 485 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। प्रदेश के 55 जिलों के एक-एक महाविद्यालयों को पीएम कॉलेज और एक्सीलोरेंस में परिवर्तित किया गया है। कौशल विकास को राज्य शासन ने प्राथमिकता पर रखा है।

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओं योजना में 8 हजार प्रशिक्षणार्थियों को 6 करोड़ 60 लाख रुपये का स्वायत्तेज प्रदान किया गया है। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख विद्यालयों में इन्क्वेशन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। राज्य में 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से 60 से अधिक नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जा रही है। इसमें 17 हजार से अधिक रोजगार के अवसर मुजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों को भरने के लिए तेजी से कार्य किया गया है। वित्तीय वर्ष 8 महीनों में शासकीय नौकरियों में 11 हजार से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 1 करोड़ 67 लाख से अधिक पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को मुख्यमंत्री जन-कल्याण संबल योजना का लाभ भी मिल रहा है। इसके लिए इस वर्ष 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के दूसरे चरण में 30 हजार 500 से अधिक श्रमिक परिवारों को 670 करोड़ रुपये से अधिक की अनुग्रह सहायता

रहा है। देश में प्रधानमंत्री मातृ-वंदना योजना में प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इस योजना में 2017 से 2024 तक 41 लाख 70 हजार बहनों को 1 हजार 150 करोड़ रुपये की राशि दी गई। प्रदेश की लगभग 90 लाख बहनों को उज्ज्वला गैस केनेशन दिए गए हैं। प्रदेश की 45 लाख 89 हजार बहनों के खाते में 450 रुपये में गैस सिलेंडर की रीफिलिंग के लिए 118 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में महिला-पुरुष के अनुपात में सुधार हो रहा है। यह अनुपात प्रति एक हजार पुरुषों पर 927 महिलाओं से बढ़कर 956 हो रहा है।

जनजातीय वर्ग के समग्र विकास और कल्याण के लिए बजट में 23 प्रतिशत अधिक राशि का प्रावधान: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनजातीय वर्ग के समग्र विकास और कल्याण के लिए इस वित्तीय वर्ष में 40 हजार 804 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, यह पिछले बजट की तुलना में 23.4 प्रतिशत अधिक है। तेन्दुपता संग्रहकों का मानदंय 3 हजार रुपये प्रति वोगा से बढ़ाकर 4 हजार रुपये कर दिया गया है। इसका सीधा लाभ लगभग 35 लाख संग्रहकों को हो रहा है। छात्रावासों के विद्यार्थियों की समस्याओं के नियोजन और मार्गदर्शन के लिए मित्र हेल्पलाइन आरंभ की गई है। साथ ही छात्रावासों में विद्यार्थियों को कम्प्यूटर रश्का भी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि हर गरीब और कमज़ोर व्यक्ति को समृद्धि और सुख की ओर ले जाना हमारा संकल्प है। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी तत्परता से कार्य किया जा रहा है।

वर्ष 2028-29 तक सिंचाई क्षमता 1 करोड़ क्षेत्रफल वाले बहनों का लक्ष्य: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत अब तक 80 लाख संग्रहकों के खाते में 1 हजार 643 करोड़ रुपये अंतरित किए गए। सरकार ने फसलों के उपजन और मर्डियों की व्यवस्था को बेतार करने के लिए भी कार्य कर दिया है। पिट्ठी परिक्षण में कृषि स्नातक युवाओं के साथ पार्टरशिप में कार्य करने की नीति बनाई गई है। कृषि प्रसंस्करण युवाओं का जाल बिछाकर स्थानीय स्तर पर ही कृषि उपज का मूल्य संवर्धन करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। श्रीआर्जुन तपादान को बढ़ावा देने के लिए लागू रानी दुर्गावती श्रीआर्जुन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किसानों के प्रति किटल 1 हजार रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। संभाग स्तर पर 10 नसरी को हाईटेक बनाने की कार्यवाही जारी है। प्रदेश के 40 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए हैं।

ममता पर बरसे प्रधान, बोले- कोलकाता की घटना को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधने हुए कहा कि परास्तातक महिला प्रशिक्ष्य चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में “राजनीति के लिए काई जगह नहीं होनी चाहिए। बनर्जी ने असरों पर लगाया था कि कोलकाता के आरजी कर मेंडिकल



कोलेज और अस्पताल में तोड़फोड़ के पीछे विपक्षी दलों का हाथ है। प्रधान ने कहा कि बनर्जी की, इस मामले में लीपापोतों का निवारण और अपाधिकारों को बचाने की कोशिश गंभीर सवाल खड़ा करती है। प्रधान ने “एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘पश्चिम बंगाल में बार-बार पूरी व्यवस्थागत विफलता देखने को मिली है।

जम्मू-कश्मीर में 18 सितंबर से वोटिंग, हरियाणा में 1 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को रिजल्ट;

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने शुक्रवार (16 अगस्त) को जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। जम्मू-कश्मीर की 90 सीटों पर फिर 1 अक्टूबर को बोल्ड वोट देखा जाएगा। दोनों राज्यों के नतीजे 4 अक्टूबर को आयोग में रिजल्ट देखा जाएगा। जम्मू-कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। सीईसी राजीव कुमार बोले- महाराष्ट्र में त्रोहार की वजह से चुनाव बाद में होंगे। उन्होंने ज्ञारखंड का जिक्र नहीं किया। हरियाणा सरकार का कार्यकाल 3 नवंबर, महाराष्ट्र का 26 नवंबर और ज्ञारखंड का 5 जनवरी को खत्म हो रहा है।



चाहते हैं कि खुद देश का भविष्य बदलने का हिस्सा बने। 4. देशभर की 46 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव समय आने पर घोषित किए जाएंगे।

